

चाबहार बंदरगाह समझौता

प्रलमिस के लयि:

[चाबहार बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय उततर-दक्षणि परविहन गलयिरा, बेलट और रोड इनशिरिटवि](#)

मेन्स के लयि:

भारत के लयि चाबहार बंदरगाह का महत्त्व, भारत और ईरान के मध्य वविदति क्षेत्तर ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [भारत और ईरान](#) ने ईरान के [चाबहार बंदरगाह](#) के संचालन के लयि **10 वर्ष** के अनुबंध पर हस्ताक्षर कयि ।

- इस दीर्घकालकि समझौते पर [इंडयिन पोर्ट्स ग्लोबल लमिटिड \(IPGL\)](#) और ईरान के [पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑरगनाइज़ेशन \(PMO\)](#) के बीच [शाहदि-बेहशिती टर्मनिल](#) के संचालन करने हेतु हस्ताक्षर कयि गए ।
- ईरान के साथ दीर्घकालकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना [मध्य एशया](#) के लयि भारत की रणनीतिक एवं आर्थकि दृष्टिका हसिसा है ।

//



चाबहार बंदरगाह भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है?

परिचय:

- चाबहार, ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह मकरान तट पर ससितान एवं बलूचसितान प्रांत में [ओमान की खाड़ी](#) में स्थित है।
- चाबहार में दो मुख्य बंदरगाह हैं, शाहदि कलंतरी एवं शाहदि बेहशिती बंदरगाह।
 - ईरान ने भारत को शाहदि बेहशिती बंदरगाह के निर्माण का प्रस्ताव दिया और भारत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

चाबहार बंदरगाह समझौते के संबंध में प्रगत:

- भारत ने मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।
- मई 2016 में भारत, ईरान एवं अफगानसितान द्वारा [अंतरराष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे](#) की स्थापना के लिये एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये, जसि चाबहार समझौते के रूप में भी जाना जाता है।
 - इस समझौते का उद्देश्य ईरान में चाबहार बंदरगाह को एक प्रमुख पारगमन बंदरगाह के रूप में उपयोग करके उक्ततीनों देशों के बीच परिवहन और व्यापार संपर्क में सुधार करना है।
 - हालाँकि, दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने में समझौते के कुछ खंडों पर मतभेद सहित कई कारकों के कारण बाधा उत्पन्न हुई।
 - भारत एक तटस्थ देश में मध्यस्थता चाहता था, जबकि ईरान अपने देश के न्यायालयों या कसिी अनुकूल देश में यह प्रक्रिया करना चाहता था।
 - विवाद का मुख्य बंदु यह था कविवादों के समाधान के लिये मध्यस्थता कहाँ की जाए। अब, दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते पर सहमत हुए हैं जो उनसे संबंधित हतियों को संतुष्ट करता है। अनुबंध में कहा गया है ककसिी भी असहमत कित्तेनों देशों के नेताओं के बीच खुले संचार और सहयोग के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिये।
- इस नवीनतम दीर्घकालिक समझौते का उद्देश्य [स्वचालित नवीनीकरण](#) प्रवाधानों के साथ 10 वर्षों की अवधि वाले प्रारंभिक अनुबंध को प्रतस्थापित करना है।

चाबहार बंदरगाह का महत्त्व:

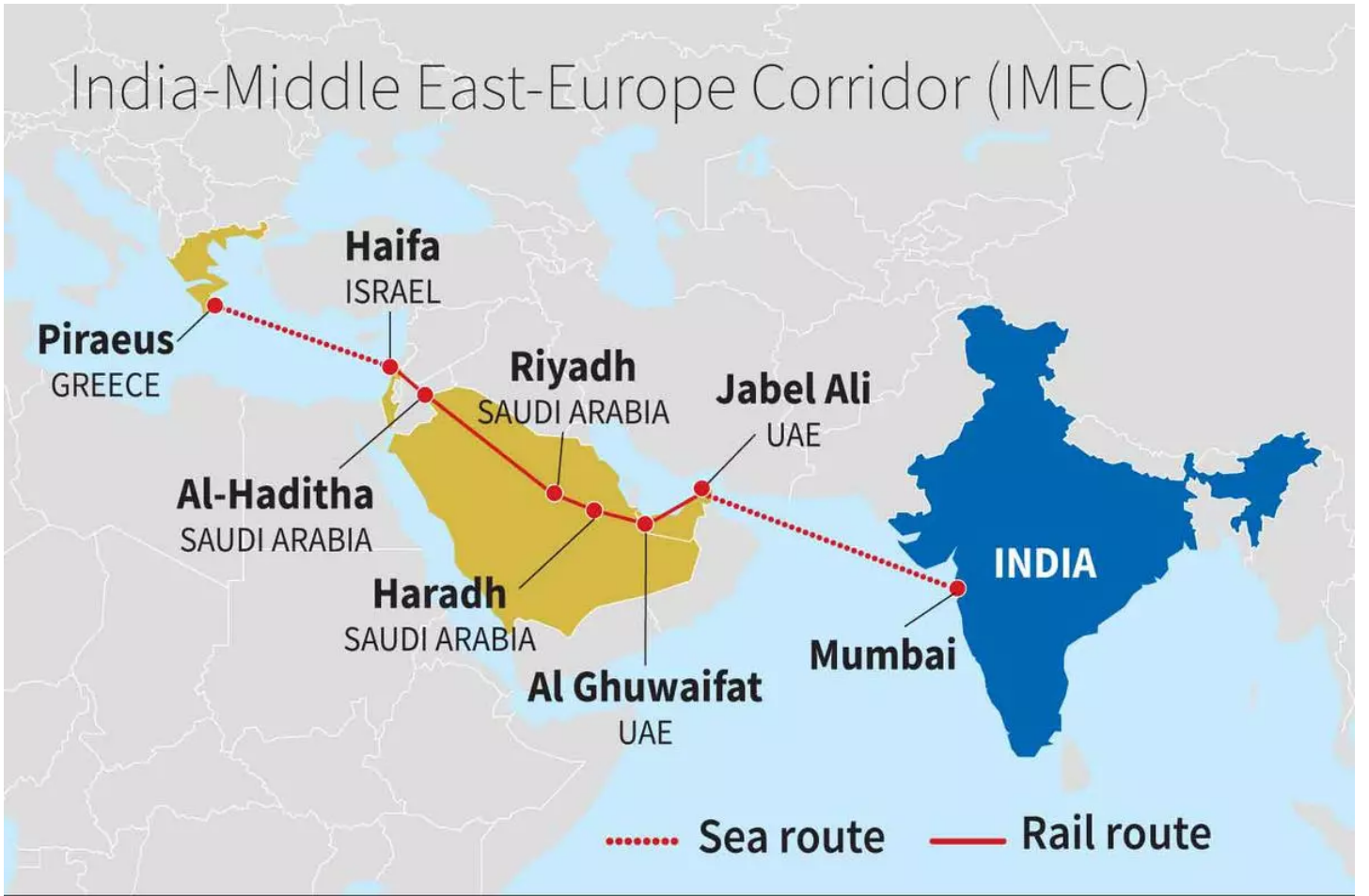
- [वैकल्पिक व्यापार मार्ग](#): ऐतिहासिक रूप से अफगानसितान और [मध्य एशिया](#) तक भारत की पहुँच काफी हद तक पाकसितान के माध्यम से पारगमन मार्गों पर निर्भर रही है।
 - चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानसितान और मध्य एशिया में व्यापार के लिये एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है, जसिके लिये भारत पहले पाकसितान पर निर्भर करता था।
 - इसके अतिरिक्त, चाबहार बंदरगाह भारत की ईरान तक पहुँच को सुवधाजनक बनाएगा, जो [अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे \(International North-South Transport Corridor-INSTC\)](#) का मुख्य प्रवेश बंदु है, जो भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप को सड़क, रेल और समुद्र के माध्यम से जोड़ता है।

- **आर्थिक लाभ:** संसाधन संपन्न मध्य एशियाई देशों और अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ाने के भारत के प्रयासों में चाबहार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
 - यह भारत को अपने व्यापारिक मार्गों में विविधता लाने तथा ईरान व अफगानिस्तान के अतिरिक्त रूस, यूरेशिया और यूरोप के बाजारों तक पहुँच बढ़ाने में सहायता करेगा।
 - **INSTC मार्ग के माध्यम से कार्गो आवाजाही से लागत में 30% और परिवहन में लगने वाले समय में 40% की बचत** होने का अनुमान है, जिससे प्रतस्पर्धी लागत में त्वरित बदलाव सुनिश्चित हो सकेगा।
 - मध्य एशियाई देश, जो संसाधनों से समृद्ध हैं, लेकिन कजाखस्तान और उज़बेकस्तान जैसे देशों, जो समुद्र तक सीधी पहुँच नहीं रखते हैं, ने **हिंद महासागर क्षेत्र** से जुड़ने तथा भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिये चाबहार का उपयोग करने में रुचि दिखाई है।
- **मानवीय सहायता:** चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान में **मानवीय सहायता** और पुनर्निर्माण प्रयासों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य कर सकता है।
 - **कोवडि-19** महामारी के दौरान चाबहार बंदरगाह ने मानवीय सहायता की आपूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
 - चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत से अफगानिस्तान तक 2.5 मिलियन टन गेहूँ और 2,000 टन दालों का निर्यात किया है।
 - वर्ष 2021 में भारत ने टैंकर्स के हमलों से निपटने के लिये बंदरगाह के माध्यम से ईरान को 40,000 लीटर पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशक मैलाथियान भेजा।
- **रणनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता:** चाबहार बंदरगाह को विकसित और संचालित करके, भारत **हिंद महासागर क्षेत्र** में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
 - चाबहार बंदरगाह चीन द्वारा पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के विकास के प्रतिकार के रूप में कार्य करेगा।
 - इसके अतिरिक्त, चाबहार में उपलब्ध डॉकगि सुविधाओं के कारण भारत **समुद्री डकैती** के मामलों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है और अरब सागर में रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम कर सकता है।

चाबहार बंदरगाह की क्षमता को साकार करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **ईरान को लेकर अमेरिका की चिंता:**
 - ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिये दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने भारत को **"प्रतर्बंधों के संभावित जोखिम"** की चेतावनी दी है।
 - तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के बाद, वर्ष 1979 से अमेरिका ने विभिन्न कानूनी प्राधिकरणों के तहत ईरान के साथ की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों पर प्रतर्बंध लगा दिया है।
 - इससे पहले वर्ष 2018 में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह की प्रगति और इसे अफगानिस्तान से जोड़ने हेतु रेलवे लिके के निर्माण में सहायता के लिये भारत को **वशिष्ट प्रतर्बंधों से छूट दी थी**।
- **हाउथी-लाल सागर संकट:**
 - हाउथी विद्रोही संचार के समुद्री मार्गों को बाधित कर सकते हैं, जिससे चाबहार बंदरगाह पर यातायात भी प्रभावित होगा।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, क्षेत्रीय तनाव:**
 - अफगानिस्तान से अमेरिका सेना की वापसी और तालिबान के पुनः वापसी के कारण वहाँ अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिसका भारत के साथ व्यापार संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
 - ईरान व उसके कुछ पड़ोसी देशों, जैसे कि इजरायल के मध्य अस्थिर संबंधों के साथ-साथ अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में अस्थिर राजनीतिक स्थितियाँ भी चाबहार बंदरगाह और भारत के आर्थिक हितों को प्रभावित कर रही हैं।
- **समान परियोजनाओं से प्रतस्पर्धा:**
 - चाबहार में कई परिवहन मार्गों से चुनौतियाँ हैं, जैसे **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor- IMEC)** जो एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ता है।

India-Middle East-Europe Corridor (IMEC)



- चीन से प्रतस्पर्द्धा:
 - चाबहार में चीन जैसे मज़बूत प्रतस्पर्द्धियों के द्वारा कथिा गया नविश, ईरान में भारत के हतियों को प्रभावति कर सकता है ।
- अवसंरचना वकिसः
 - चाबहार परयोजना का उद्देश्य बंदरगाहों, सड़कों एवं रेलवे जैसे बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है, जिसके लयि महत्त्वपूर्ण नविश, समय तथा वशिषज्जता की आवशयकता है । कोई भी देरी या अक्षमता इसकी प्रगति में बाधा बन सकती है ।

भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों की स्थतिक्या है?

- वत्ति वर्ष 2022-23 के दौरान भारत-ईरान द्वपिक्षीय व्यापार 2.33 बलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष-दर-वर्ष 21.76% की वृद्धि दर्शाता है ।
- ईरान को भारत का नरियात 1.66 बलियन अमेरिकी डॉलर था और ईरान से भारत का आयात 672.12 मलियन अमेरिकी डॉलर था ।
- पछिले वर्ष के इसी आंकड़े की तुलना में कुल व्यापार में 23.32% की कमी आई ।
- भारत, ईरान को मुख्य रूप से कृषि उत्पाद एवं पशु उत्पाद जैसे-मांस, दुग्ध उत्पाद, प्याज, लहसुन तथा डबिबाबंद सब्जियाँ नरियात करता था ।
- ईरान से आयात में मथिाइल अल्कोहल, पेट्रोलियम बट्टिमेन, तरलीकृत ब्यूटेन, तरलीकृत प्रोपेन, सेब, खजूर और बादाम शामिल थे ।
- अप्रैल 2000 से दसिंबर 2023 तक ईरान से भारत में FDI प्रवाह केवल 1 मलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज कथिा गया ।
- भारत वर्तमान में ईरानी तेल का आयात नहीं करता है क्योंकि ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) के प्रतबिंधों के अधीन है ।

???????? ???? ?????:

रूस और यूरेशिया के साथ भारतीय संपर्क को अनुकूल बनाने के लयि INSTC और चाबहार पोर्ट एक दूसरे के पूरक कैसे सिद्ध होंगे?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है?(2017)

- (a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी ।
- (b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे ।
- (c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिये भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा ।
- (d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा ।

उत्तर: C

??????:

प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रतिक्रिया रवैया अपनाना चाहिये? (2018)

प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगतिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है । पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये । (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chabahar-port-agreement>

